जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 | वर्षः 17 | संख्याः 264 | प्रभात | चूरू, मंगलवार 20 जनवरी, 2026 | पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 | पृष्ठ 6 | मूल्य 2.50 रु.

कांग्रेस में सभी संगठनात्मक परिवर्तन केरल चुनाव के बाद में ही होंगे

इसका प्रमुख कारण है, के.सी. वेणुगोपाल, वे केरल में मु.मंत्री बनने को लालायित हैं, अभी राहुल के निकटतम व्यक्ति होने के कारण, वेणुगोपाल ही, परोक्ष रूप से कांग्रेस चला रहे हैं

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 जनवरी। राहुल गांधी इस समय केरल और के.सी. वेणुगोपाल के बीच फंसे हुए हैं।

राहुल गांधी के लिए केरल जीतना इस वक्त की उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जीत के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि के.सी. वेणुगोपाल को केरल का मुख्यमंत्री बनाया जाए या नहीं।

इसी फैसले पर पार्टी के भीतर कई अन्य निर्णय भी निर्भर करते हैं, जैसे के.सी. जाएंगे या वहीं बने रहेंगे।

सूत्रों का कहना है कि केरल चुनावों तक के लिए पार्टी के सभी संगठनात्मक फैसलों को टाल दिया गया है। एक वरिष्ठ नेता, जो शीर्ष स्तर की गतिविधियों से वाकिफ हैं, ने कहा कि राहुल गांधी का

- वेणुगोपाल के रूतबे का यह हाल है कि कांग्रेसाध्यक्ष खड़गे भी उनके सामने मुँह नहीं खोलते और वो ही काम करते हैं, जो वेणुगोपाल इशारा करते हैं।
- अतः वेणुगोपाल अगर केरल जाते हैं तो कांग्रेस में एकदम नए सिरे से समीकरण बनेंगे।
- यहाँ तक कि पहले यह माना जा रहा था कि 14 जनवरी के बाद, राहुल गांधी पार्टी में भारी-भरकम तब्दीलियां करेंगे। पर, स्वयं राहुल ने भी अब यह निर्णय टाल दिया है और केरल के विधानसभा चुनावों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया है।
- पहले तो वेणुगोपाल चुनाव के पहले ही केरल जाना चाहते थे, पर, उन्हें समझाया गया कि अगर वे चुनाव पहले गए तो सभी दिग्गज़ उनको हराने में जुट जाएंगे। इस तर्क को स्वीकार करते हुए, वेणुगोपाल ने चुनाव के बाद केरल जाना ही श्रेयस्कर माना।
- अतः, जब तक केरल के चुनाव नहीं होते, वेणुगोपाल का केरल मु.मंत्री पद पर जाना या ना जाना स्थगित है और इसीलिए कांग्रेस में संगठन परिवर्तन की फाइल ठंडे बस्तें में है।

पूरा ध्यान सिर्फ केरल जीतने पर है।

यह भी पता चला है कि के.सी. वेणुगोपाल चुनाव से पहले ही केरल भेजे जाने को लेकर काफी उत्सुक थे, लेकिन कुछ शुभचिंतकों ने उन्हें इंतज़ार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नितिन नबीन निर्विरोध भाजपा अध्यक्ष निर्वाचित

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 जनवरी। भाजपा के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सोमवार को केवल बिहार के 45 वर्षीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के ही नामांकन पत्र दाखिल किए गए। निर्वाचन अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण ने घोषणा की कि चूंकि शीर्ष पार्टी नेताओं ने केवल नितिन नबीन का ही नामांकन दाखिल किया है, इसलिए वे निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाते हैं।

नितिन नबीन के भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने की औपचारिक घोषणा मंगलवार को

- औपचारिक घोषणा भाजपा मुख्यालय में मंगलवार 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में होगी।

सुबह 11.30 बजे पार्टी मुख्यालय में की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी के. लक्ष्मण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में इसकी घोषणा करेंगे।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं नितिन नबीन के पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के समारोह में उपस्थित रहना चाहते थे।

निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा वरिष्ठ नेताओं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मणिकर्णिका घाट के डोम राजा की अर्ज़ी भारी पड़ेगी भाजपा को?

डोम राजा विश्वनाथ चौधरी ने प्र.मंत्री पर दबाव डाला था कि इस घाट का भी काशी विश्वनाथ कोरिडोर की भांति आधुनिकीकरण करवा दें

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 जनवरी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास योजना की शुरुआत ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, जिसका असर अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा की संभावनाओं पर प्रतिकूल रूप से पड़ सकता है।

इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2023 में किया था, लेकिन इसका वित्तपोषण (फंडिंग) काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और इसे "रूप फाउंडेशन" नामक संस्था द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

मणिकर्णिका तीर्थ कॉरिडोर विकास परियोजना के तहत, बुलडोज़र चलाए जाने और ऊँची "मढ़ी" (ऊंचे चबूतरे) से मूर्तियों को हटाकर गिराए जाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इसके बाद इतिहासकारों, अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट और पाल समुदाय जैसे धार्मिक

- आधुनिकीकरण का प्लान पहले 3000 वर्ग मीटर तक सीमित था, फिर बढ़ाकर 39,350 वर्ग प्लेटफॉर्म बनाना तय किया गया
- यह आधुनिकीकरण का प्लान चार चरणों में पूरा होना है और प्लेटफॉर्म बनने के बाद, एक साथ 19 दाह संस्कार किए जा सकेंगे, तथा इसके लिए कई तरह की सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
- पर, प्रोजैक्ट की प्रथम दिन से ही आलोचना शुरु हो गई, इतिहासकार, धार्मिक ग्रुप्स जैसे अहिल्या बाई होल्कर ट्रस्ट, पाल समाज तथा कांग्रेस व समाजवादी पार्टियों द्वारा।
- इतिहासकार, मृदुला मुखर्जी के अनुसार, जनता में यह भय फैला है कि धार्मिक पवित्र स्थलों का व्यवसायिकीकरण हो रहा है तथा यह भी प्रचारित हो रहा है कि मणिकर्णिका घाट से सटे हुए ही व्यवसायिक मॉल व अन्य बड़े-बड़े कॉमर्शियल स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे।

संगठनों, तथा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत, विपक्षी दलों की ओर से इसकी तीखी आलोचना की गई।

पुनर्विकास के नाम पर आगे किसी भी तरह के ध्वस्तीकरण को रोकने के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'ग्रीनलैंड के बारे में उनकी सोच की वजह से उन्हें नोबल प्राइज़ नहीं दिया गया'

एक बच्चे की तरह मचलते हुए, ट्रंप ने "दोषी" यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 जनवरी। एक चालाक "टीन एजर" (किशोर) की तरह, डॉनल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि नोबेल समिति ने उन्हें शांति पुरस्कार इसलिए नहीं दिया, क्योंकि वे ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के पक्षधर हैं।

किसी और को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने से असंतुष्ट राष्ट्रपति ट्रंप अब यह मान चुके हैं कि यह सम्मान उनसे पूरी तरह दूर है और इसका कारण वे ग्रीनलैंड को वहाँ की जनता और डेनमार्क से, किसी भी तरीके से, हासिल करने के अपने रुख को बता रहे हैं।

इसी बीच, अपनी इस कोशिश के खिलाफ बढ़ते विरोध को देखते हुए ट्रंप ने झुंझलाहट में उन यूरोपीय देशों पर अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) लगाने की

- यूरोपीय देशों ने जवाबी कार्यवाही करते हुए, अमेरिका द्वारा यूरोप निर्यात सामान पर 108 बिलियन डॉलर का टैरिफ लगाया।
- फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों इस कार्यवाही में अगुवा बने हुए हैं, तथा अमेरिका से सदा "विशेष रिश्ते" की दुहाई देने वाले देश इंग्लैण्ड ने भी मैक्रों को पूरा समर्थन देने का निर्णय लिया।
- पहला असर तो यह हुआ कि हर बार की तरह, इस संकट व अनिश्चय की स्थिति में डॉलर की तुलना में सोना महँगा हुआ।

घोषणा कर दी, जिन्होंने उनके इस कदम का विरोध किया था। इसका यूरोप में व्यापक रूप से विरोध किया गया है।

अब यूरोप अमेरिका से आयात होने वाले 108 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दे रहा है। यूरोप के कई नेताओं ने अलग-अलग तौर पर उन देशों पर नए टैरिफ लगाने की ट्रंप की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई पेपर लीक आरोपी जगदीश विश्नोई को जमानत मिली

जयपुर, 19 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में आरोपी जगदीश विश्नोई को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश जगदीश विश्नोई की द्वितीय जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने

- हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में अधिकतम तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है और आरोपी 22 माह से जेल में है।

अपने आदेश में कहा कि मामले में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन का प्रयोग अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत, अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है और याचिकाकर्ता 22 माह से जेल में बंद है। वहीं मुख्य आरोपी राजेश खंडेलवाल को पूर्व में जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा, प्रकरण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'शिव सेना ने मुम्बई को 23 मराठी मेयर दिए हैं, क्या यह परम्परा कायम रहेगी'

शिव सेना (यूबीटी) ने सामना के जरिए शिंदे को मुम्बई में शिव सेना का मेयर बनवाने की चुनौती दी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 जनवरी। बीएमसी (बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन) चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद मुंबई में एक बार फिर "रिज़ॉर्ट राजनीति' लौट आई है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने कहा है कि नगर निगम चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन असली राजनीति अभी बाकी है।"

बीएमसी चुनावों में भाजपा ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जबकि ठाकरे परिवार को अपने गढ़ में झटका लगा है। लेकिन अब सबकी नजरें शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिकी हैं।

2022 में शिवसेना में बगावत कर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार गिराने वाले एकनाथ शिंदे अब भाजपा के सहयोगी हैं और इस नगर निगम चुनाव में उनकी

- एकनाथ शिंदे भारी दबाव में है, इसलिए नतीजे घोषित होते ही उन्होंने अपनी पार्टी के पार्षदों को फाइव स्टार होटल में शिफ्ट कर दिया है।
- शिंदे आशंकित हैं कि भाजपा उनके पार्षदों को तोड़ सकती है, जो एक बार दलबदल कर सकते हैं, वो दोबारा भी कर सकते हैं।
- बीएमसी चुनावों में भाजपा ने शानदार 89 सीटें जीती हैं, पर, बहुमत के लिए उसे शिंदे का साथ अवश्य चाहिए, इसलिए शिंदे भाजपा पर दबाव डाल रहे हैं।

पार्टी ने 29 सीटें जीती हैं। नतीजों के बाद जश्न और राजनीतिक बयानबाजी के बीच, शिंदे गुट ने अपने पार्षदों को मुंबई के एक पांच सितारा होटल में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जिससे शहर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को दौर शुरु हो गया।

जब चुनावी नतीजे राजनीतिक पुनर्संयोजन की संभावनाएं पैदा करते हैं, तब "रिज़ॉर्ट राजनीति" सामने आती है। शिंदे टीम के इस कदम को समझने के लिए बीएमसी के आंकड़ों पर नज़र डालना जरूरी है। कुल 227 वार्ड वाली बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है। भाजपा ने 89 सीटें जीती हैं और शिवसेना (शिंदे गुट) को 29 सीटें मिली हैं। दोनों मिलकर 118 सीटों पर काबिज हैं, जो बहुमत से ज्यादा है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसने अकेले चुनाव लड़ा था, ने तीन वार्ड जीते हैं और वह भी अपने सहयोगियों का समर्थन कर सकती है।

दूसरी ओर, शिवसेना (यूबीटी), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और एनसीपी (शरद पवार) को क्रमशः 65, छह और एक वार्ड मिले हैं। यह संख्या कुल मिलाकर 72 होती है। कांग्रेस ने 24, एआईएमआईएम ने आठ और समाजवादी पार्टी ने दो वार्ड जीते हैं। यदि विपक्ष एकजुट हो जाए तो कुल संख्या 106 हो जाएगी, जो बहुमत से आठ कम है। हालांकि, इन दलों की राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए यह संभावना कम है, फिर भी इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

नई दिल्ली, 19 जनवरी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चल रहे मतदाता सूची के (एसआईआर) को लेकर चर्चा तेज

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन सवा करोड़ मतदाताओं के नाम सार्वजनिक किए जाएं, जिनके नामों पर चुनाव आयोग को आपत्ति है। यह लिस्ट ग्राम पंचायत भवनों, ब्लॉक कार्यालयों आदि में लगाई जाए ताकि सब पढ़ सकें।

होती ही जा रही है। इसी बीच इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग (ईसी) को अहम निर्देश दिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत का ट्रंप के गाज़ा पुनर्निमाण बोर्ड की सदस्यता के बारे में अनिर्णय किसी अनिश्चय व टालम-टोल नीति की निशानी नहीं है

ट्रंप सदा से यूएन को फुंका हुआ कारतूस बताते रहे हैं, अतः ट्रंप द्वारा प्रस्तावित बोर्ड, यूएन में सुधार करने का प्रयास नहीं है, बल्कि उसको खत्म कर एक "ट्रंप यूएन" बनाने की कोशिश है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र संघ को ट्रंप द्वारा अप्रासंगिक बताकर खुले आम खारिज करने के बाद, नई दिल्ली अमेरिका-नेतृत्व वाले शांति तंत्र को वैधता देने से हिचक रही है, जो बहुपक्षीय मानदंडों में सुधार करने के बजाय उन्हें दरकिनार करता हुआ प्रतीत होता है।

गाज़ा के लिए प्रस्तावित बोर्ड ऑफ़ पीस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शामिल होने के लिए डॉनल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर भारत की सोची-समझी चुप्पी ही इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि इस पहल को "ट्रंप संयुक्त राष्ट्र" क्यों कहा जा रहा है। नई दिल्ली के लिए मुद्दा सिर्फ़ गाज़ा या युद्धोत्तर पुनर्निमाण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं गहरी बेचैनी एक ऐसे वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रीय शासन ढांचे को लेकर महसूस की जा रही है, जिसे एक अमेरिकी राष्ट्रपति बढ़ावा दे रहे हैं और जो बार-बार और सार्वजनिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को "खत्म हो चुकी शक्ति" बता रहे हैं। जब संयुक्त राष्ट्र के प्रति इस

- यूएन में कितनी भी कमियां हों, पर, कम से कम यूएन एक कायदे-कानून पर काम करने वाली संस्था है। "ट्रंप" का यूएन केवल एक नेता व एक "शक्तिशाली" देश द्वारा संचालित व्यवस्था है, जो बड़ी खतरनाक स्थिति है।
- भारत अभी सार्वजनिक रूप से ट्रंप के इस अजीबोगरीब प्रस्ताव का खुल्लम-खुल्ला विरोध करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि, स्वयं भारत कई व्यापारिक मसले टैरिफ आदि के विवादों में में फंसा है, अतः भारत द्वारा ट्रंप के प्रस्ताव पर चुप्पी रखना ही समझदारी पूर्ण निर्णय है।

घोषित संदेह को खुद ट्रंप की अध्यक्षता वाले अमेरिका-नेतृत्व वाले, नेता-केन्द्रित शांति निकाय के साथ तुलनात्मक रुप से देखा जाता है, तो भारतीय नीति-निर्माताओं के लिए यह प्रस्ताव किसी तकनीकी व्यवस्था की बजाय बहुपक्षवाद में सुधार के बजाय उसे हटाने का राजनीतिक बयान बन जाता है।

भारतीय दृष्टिकोण से यह बेहद अहम है। भारत लंबे समय से यह कहता आया है कि संयुक्त राष्ट्र त्रुटिपूर्ण, अल्प-प्रतिनिधित्व वाला है और उसमें तत्काल सुधार की ज़रूरत है, खासकर उसमें ग्लोबल साउथ की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना जरुरी है। लेकिन भारत यह भी उतनी ही स्पष्टता से कहता रहा है कि समाधान संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के पुनर्गठन में है, न कि उसे खोखला करने या एक शक्ति या एक व्यक्ति के प्रभुत्व वाले समानांतर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी आज रायबरेली में

नयी दिल्ली, 19 जनवरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगे और वहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान, वे "मनरेगा बचाओ" चौपाल में हिस्सा लेते हुए कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे।

अपने रायबरेली दौरे के दौरान गांधी सबसे पहले सुबह रायबरेली के

- यहां वे मनरेगा बचाओ चौपाल में हिस्सा लेंगे और रायबरेली प्रीमियर लीग का शुभारंभ करेंगे।

भुएमऊ गेस्ट हाउस में प्रतिनिधिमंडलों और मतदाताओं से मुलाकात कर मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा करेंगे। उसके बाद वे गेस्ट हाउस में सांसद निधि द्वारा किए गए कार्यों का उद्घाटन करेंगे और बाद में रायबरेली युवा खेल अकादमी द्वारा आयोजित रायबरेली प्रीमियर लीग (टी-20) क्रिकेट टूर्नामेंट का राजीव

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)